पूर्वोत्तर अब 'लैंडलिंक्ड पावरहाउस

मेघालय में 233 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, सोहरा सर्किट बनेगा पर्यटन हब

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीता दशक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिवर्तन का प्रतीक रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह क्षेत्र अब लैंडलॉक्ड नहीं, बल्कि लैंड-लिंक्ड पावरहाउस बन चुका है.सिंधिया ने यह बात मेघालय में प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन) योजना के तहत इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट की आधारशिला रखते हुए कही. इस अवसर पर उन्होंने 233 करोड़ रुपये के कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया.

उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अब तक 6.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता नीति के तहत आवंटित की गई है, जिससे कनेक्टिविटी, उद्यम और सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं.मेघालय को इस नीति का विशेष लाभ मिला है. कोविड के बाद राज्य ने 12 से 16 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है. सिंधिया ने 22,864 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 166.8 किमी लंबे शिलांग-सिलचर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और उमरॉय एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को पूर्वोत्तर के विकास का महत्वपूर्ण कदम बताया.

> सिंधिया ने कहा कि नया शिलांग शहर स्मार्ट-ग्रीन टाउनशिप और ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होगा. इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट 650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सोहरा को एक बहुदिवसीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है. परियोजना में सोहरा अनुभव केंद्र, नोहकालिकाई फॉल्स प्रीसिंक्ट, मावसमाई इको पार्क और 'सेवन सिस्टर्स फॉल्स' व्यूपॉइंट जैसे प्रमुख आकर्षण शामिल हैं. ये योजनाएँ हजारों रोजगार सृजित करेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देंगी.

सोने में आई गिरावट चांदी रु. 1100 उछली

नई दिल्ली, 2 नवंबर. घरेलू सर्राफा बाजार में कारोबार के दौरान सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत में 1,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक की जोरदार तेजी आई. हालांकि, साप्ताहिक आधार पर देखा जाए तो दोनों ही कीमती धातुओं में कमजोरी का रुख बना हुआ है. सोने के भाव 260 रुपये से 290 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ते हुए. इस कमजोरी के बाद देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,23,000 रुपये से लेकर 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,12,750 रुपये से 1,12,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज की गई. इसके विपरीत, चांदी के भाव में उछाल आने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 1,52,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है.

त्योहारी मांग और टैक्स राहत से उद्योग बूस्ट

- **यात्री वाहनों की थोक बिक्री 4.70 लाख यूनिट्स पर**
- **बिक्री में सालाना आधार पर 17.23% की बढ़त दर्ज**
- **यह अब तक की सबसे ऊँची मासिक बिक्री**

नई दिल्ली. देश में यात्री वाहनों (पीवी) की थोक बिक्री ने अक्टूबर महीने में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर छू लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग के आंकड़ों का हवाला देते हुए रविवार को इसकी जानकारी दी. बिक्री में यह उछाल जीएसटी सुधारों और त्योहारी सीजन की मजबूत मांग के कारण आया है.

उद्योग डेटा के अनुसार, अक्टूबर में यात्री वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 17.23

प्रतिशत बढ़कर 4,70,227 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 4,01,105 यूनिट्स था.

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर लिखा कि अक्टूबर में मात्रा के हिसाब से भारत की यात्री वाहन इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने पुष्टि की कि यह अब तक की सबसे अच्छी घरेलू मासिक बिक्री है, जिसने जनवरी 2025 में दर्ज किए गए 4,05,522 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

जानकारों का मानना है कि जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन में दिए गए आकर्षक ऑफर्स ने ग्राहकों को बड़ी संख्या में कारें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके परिणामस्वरूप कई वाहन निर्माताओं ने अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की.

इस रिकॉर्ड तोड़ बिक्री में प्रमुख ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने शानदार प्रदर्शन किया. किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में प्रवेश के बाद से अक्टूबर में 29,556 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक प्रदर्शन हासिल किया. इसी तरह, स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अक्टूबर में 8,252 यूनिट्स बेचकर अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की.

भारतीयों का मॉल प्रेम

कपड़े और खाना बने भारतीय शॉपर्स की टॉप पसंद

नयी दिल्ली, 02 नवंबर (वार्ता) शॉपिंग मॉल और शहरों के बड़े बाजारों में भारतीय सबसे ज्यादा पैसा परिधानों पर और उसके बाद खाने-पीने पर खर्च करते हैं.

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, देश में शॉपिंग सेंटरों का कुल कारोबार लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें 30-35 (1,500-1,700 अरब रुपये) प्रतिशत कमाई परिधानों की बिक्री से होती है. इसके बाद मुख्य बाजारों का कारोबार लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये का है. इसमें 32-35 प्रतिशत पैसा (1,200-1,400 अरब रुपये) लोग परिधानों पर खर्च करते हैं.

परिधानों के बाद दूसरे नंबर पर खाने-पीने की चीजें हैं. मॉलों में अपने कुल खर्च का 20-25 प्रतिशत (1,000-1,100 अरब रुपये) लोग खाने-पीने पर खर्च डालते हैं. वहीं, बड़े बाजारों में लोग 800-950 अरब रुपये (22-25 प्रतिशत) इस मद में खर्च कर डालते हैं.

नाइट फ्रैंकफर्ट द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के हवाई अड्डे भी धीरे-धीरे बड़े रिटेल सेंटरों में बदलते जा रहे हैं. हवाई अड्डों पर रिटेल क्षेत्र का राजस्व 10,000 करोड़ रुपये है और यहां लोग सबसे अधिक 45-54 अरब रुपये (38-47 प्रतिशत) खाने-पीने पर खर्च करते हैं जबकि परिधान और एक्सेसरीज 30-35 अरब रुपये (28-32 प्रतिशत) के साथ दूसरे स्थान पर रहा. तीनों तरह के रिटेल शॉपिंग प्लेस में सौंदर्य एवं आरोग्य उत्पादों का स्थान रहा.

ईपीएफओ ने लॉन्च की कर्मचारी नामांकन योजना

योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी खुली

नियोक्ताओं को देना होगा सिर्फ अपना अंशदान और 100 रु. जुर्माना

नई दिल्ली. देश में कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी नामांकन योजना-2025 की शुरुआत की है.

श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर यह योजना लॉन्च की. मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह योजना नियोक्ताओं को उन पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने के

> इस योजना का लाभ उठाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ ईपीएफओ द्वारा कोई स्वत: संज्ञान लेकर अनुपालन कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस पहल से कार्यबल के औपचारिकरण और व्यापक ईपीएफ कवरेज में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे सबके लिए सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को बल मिलेगा.

लिए एक विशेष अवसर प्रदान करती है, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से छूट गए थे. इसके माध्यम से नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अपने पिछले अनुपालन को नियमित कर सकते हैं. यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक यानी छह महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी. इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक ईपीएफ समावेशन को बढ़ावा देना और पुरानी चूक को नियमित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है. नियोक्ताओं को बड़ी राहत इस योजना के तहत सभी प्रतिष्ठान पात्र हैं. ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, यदि कर्मचारी का हिस्सा पहले नहीं काटा गया था, तो उस अंशदान को माफ कर दिया गया है.

नियोक्ता का दायित्व सीमित रहेगा. उन्हें केवल अपना (नियोक्ता का) अंशदान, ब्याज (धारा 7Q), प्रशासनिक शुल्क और सिर्फ 100 रुपए का सांकेतिक दंडात्मक हर्जाना जमा करना होगा. यह 100 रुपए का एकमुश्त जुर्माना तीनों ईपीएफ योजनाओं के लिए पूर्ण अनुपालन माना जाएगा. ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ अधिनियम की धारा 7ए, पैरा 26बी, या ईपीएस-1995 के पैरा 8 के तहत पहले से ही जांच चल रही है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और उन पर हर्जाना 100 रुपए तक ही सीमित रहेगा.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में मक्का पर खींचतान

ट्रेड टॉक्स में तनातनी-मक्का मुद्दे पर भारत ने दिखाई सख्ती

भारत बोला - मक्का पर समझौता नहीं, किसानों का हित पहले

नयी दिल्ली, 02 नवंबर. मक्का आयात को लेकर अमेरिका की ओर से दबाव के बावजूद भारत अपने किसानों के पक्ष में मज़बूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल- दोनों साफ़ कर चुके हैं कि भारतीय किसानों हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

दोनों देशों के बीच इस समय चल रही व्यापार वार्ताओं में अमेरिका की ओर से, खास कर कृषि उपजों के भारतीय बाजार को खोलने का मुद्दा उठता रहा है. हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने वाशिंगटन पत्रकारों से बातचीत में भारत के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा था, भारत कहता है कि उसकी आबादी 1.4 अरब की है, तो क्या ये 140 करोड़ लोग अमेरिका का एक बुशल (लगभग 25 किलो) मक्का भी नहीं खरीद सकते? वे हमें भी चीजें बेचते हैं, लेकिन हमारे माल पर भारी भरकम आयात शुल्क लगा देते हैं, क्या यह उचित है?

अमेरिकी मंत्री लुटनिक की हताशा के पीछे दो प्रमुख कारण बताये जा रहे हैं. एक तो अमेरिका में इस बार मक्के की बम्पर पैदावार हुई है और दूसरे, चीन ने मक्के का आयात घटा दिया है.

मक्का पैदावार बनी अमेरिका की चिंता

अमेरिकी मक्के के सबसे बड़ा खरीदार चीन ने इसकी खरीद में भारी कटौती कर रखी है. चीन पहले अमेरिकी सोयाबीन का भी प्रमुख आयातक था, लेकिन हाल के वर्षों में उसने वहां से सोयाबीन का आयात कम कर दिया था. बीते साल अमेरिका के कुल सोयाबीन निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत चीन ने खरीदा था, पर इस बार अभी कोई सौदा नहीं हुआ है. इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी किसानों ने सोयाबीन की जगह मक्का की बुवाई बढ़ा दी है. इससे अब मक्का पैदावार अमेरिका की चिंता बन चुकी है. मक्के का निर्यात घटने से वहां कीमतें नीचे जाने लगेंगी और मक्के के भंडार भर चुके हैं.

चावल, दाल, खाद्य तेलों में साप्ताहिक गिरावट

गेहूं और चीनी के दाम कमोबेश स्थिर रहे

नयी दिल्ली, 02 नवंबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव घट गये. दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट रही जबकि गेहूं और चीनी के दाम कमोबेश स्थिर रहे. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 38 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,826 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी.

गेहूं 2,859.91 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रहा.

आटे की कीमत छह रुपये गिरकर 3,318.60 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी.

बीते सप्ताह सरसों तेल की औसत कीमत 111 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी. पाम ऑयल में 18 रुपये की गिरावट रही. मूंगफली तेल 85 रुपये और सोया तेल 21 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ. सूरजमखी तेल की कीमत 14 रुपये और वनस्पति की 28 रुपये प्रति क्विंटल घट गयी.

दाल-दलहनों में मसूर दाल की औसत कीमत में 29 रुपये प्रति क्विंटल की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गयी. चना दाल की कीमत 13 रुपये और मूंग दाल की 50 रुपये प्रति क्विंटल घट गयी.

भारत-जापान की टैक्स सेटलमेंट प्रक्रिया को OECD अवॉर्ड

नयी दिल्ली, 02 नवंबर. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने भारत और जापान को कंपनियों की बहुराष्ट्रीय विनिर्माण श्रृंखला में कीमतों के अंतरण संबंधी मामलों के समाधान की परस्पर सहमति की प्रक्रिया के अच्छे नतीजों लिए 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया है. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते में सर्वश्रेष्ठ द्विपक्षीय सहयोग के लिए ओईसीडी के कर प्रशासन मंच का यह पुरस्कार देशों को अंतराष्ट्रीय कर विवादों को पारस्परिक रूप से हल करने के श्रेष्ठ कार्यों का बहुपक्षीय स्तार पर सम्मान है.

भारतीय बाजार में उछाल

4 कंपनियों का मूल्य बढ़ा रु .95,447 करोड़

मुंबई, 02 नवंबर. शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही गिरावट के बीच बीएसई की शीर्ष 10 में शामिल चार कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 95,447 करोड़ रुपये बढ़ गया जबकि अन्य छह के संयुक्त एमकैप में 91,686 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी.

विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप सबसे अधिक 47,431 करोड़ रुपये बढ़ी और उसका बाजार पूंजीकरण सप्ताह के दौरान 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. भारतीय स्टेट बैंक का एमकैप 30,092 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल का 14,540 करोड़ रुपये और भारतीय जीवन बीमा निगम का 3,384 करोड़ रुपये बढ़ा. बाजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक 29,090 करोड़ रुपये घट गया. आईसीआईसीआई बैंक के एमकैप में 21,619 करोड़ रुपये और इंफोसिस में 17,822 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी.

समाचार विशेष

फिर चुनाव मैदान में उतरे हरिनारायण सिंह

पटना. कहते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं. कोई रिकॉर्ड टूटते हीए नया कीर्तिमान बन जाता है. ऐसा ही एक अनोखा कीर्तिमान इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बनने की प्रबल संभावना है. इस दहलीज पर कोई दिग्गज, बाहुबली या रसूखदार नहीं बल्कि सादगी भरी राजनीति करने वाले हरिनारायण सिंह खड़े हैं.

नालांदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट एक ऐसे रिकॉर्ड का गवाह बनने को तैयार है जो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी के नसीब में नहीं आ पाया है. ऐसा तब भी नहीं हो पाया, जब झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था. यह कीर्तिमान रचने के लिए कमर कस चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमारी की पार्टी जेडीयू से विधायक हरिनारायण सिंह.

10वीं जीत के लिए मैदान में- नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी. ये विश्वविद्यालय उस वक्त दुनियाभर से छात्रों के शिक्षा का केंद्र थाए जब पूरी दुनिया में शिक्षण संस्थान की कहीं कोई परिकल्पना तक नहीं थी. इसी नालंदा की जमीन से हरिनारायण सिंह 10वीं बार विधायक बनने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं. इससे पहले वो नौ बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं. अगर वो 10वीं बार चुनाव जीतते हैं तो ऐसा करने वाले बिहार की राजनीति के पहले नेता होंगे. हरिनारायण सिंह के साथ दो और नेताओं के नाम बिहार में नौ.नौ बार विधायक बनने का रिकॉर्ड दर्ज है. सदानंद सिंह और रमई राम ने नौ.नौ बार विधायक बनने का कारनामा तो कियाए लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं. यानीए अब उनके नाम नया कीर्तिमान होने की संभावना ही नहीं बच पाई. रमई राम कांग्रेसए जनता दलए लोक दलए जेडेयी और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े थे. हरिनारायण सिंह साल 1977, 1983, 1990, 2000, 2005 (फरवरी, 2005;अक्टूबर) 2010, 2015 और साल 2020 में नौ बार चुनाव जीत चुके हैं.

हरिनारायण नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव

नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले हरिनारायण सिंह इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे. वो अपनी जगह बेटे को चुनाव मैदान में उतारना चाहते थेए लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और हरिनारायण सिंह को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरना पड़ा. हालांकि 2020 के पिछले चुनाव में ही हरिनारायण सिंह ने उम्र का हवाला देते हुए अपनी जगह बेटे को टिकट दिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी नीतीश के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा था.

मुस्लिम वोट इस बार चौंकाएगा!

मुस्लिम वोट के तीन दावेदार इस बार चुनाव में

पटना. बिहार में किसी पार्टी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में टिकट नहीं दी है. मुस्लिम और यादव समीकरण पर चुनाव लड़ने वाली लालू प्रसाद की पार्टी राजद ने 18 फीसदी आबादी वाले मुसलमानों को 18 सीटें दी हैं, जबकि 14 फीसदी आबादी वाले यादवों को 52 सीटें दी हैं.

राजद की सहयोगी कांग्रेस ने भी 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. उधर एनडीए में इस बार मुस्लिम मतदाताओं से मोहभंग है तभी गठबंधन की ओर से 243 में से सिर्फ पांच सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं. पिछले चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवार देने वाले नीतीश कुमार ने भी इस बार सिर्फ चार उम्मीदवार दिए हैं.

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया एमआईएम ने आबादी के अनुपात में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट के तीन दावेदार इस बार चुनाव में हैं. राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के अलावा ओवैसी की पार्टी एमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज.

राजद ने यादवों के मुकाबले एक तिहाई सीटें दीं

यह बहुत दिलचस्प है कि मुस्लिम वोट बिखर सकता है और ऐसा होने के कई कारण हैं. पहला कारण तो यह धारणा है कि महागठबंधन इस बार भी एनडीए को नहीं रोक पाएगा. मुसलमानों को लग रहा है कि जब एनडीए को रोकना मुश्किल है तो क्यों नहीं वे अपने विधायकों की संख्या बढ़ाएं और अपना नेतृत्व तैयार करें. दूसरा कारण यह है कि मुस्लिम और यादव समीकरण बनाने वाले राजद ने ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों को यादवों के मुकाबले एक तिहाई सीटें दीं. तीसरा कारण यह है कि तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित हो गए और ढाई फीसदी मल्लाह आबादी वाले नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करा दिया लेकिन 18 फीसदी वाले मुसलमानों में से उप मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कराई.

सबको पता है कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट करने का एक ही पैमाना है. पूरे देश में वही पैमाना काम करता है.

3 विधायकों का पार्टी ने काटा टिकट

टिकट न मिलने से घर बैठे विधायक

औरंगाबाद. राजद की राजनीति में सक्रिय तीन विधायकों को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. विधानसभा चुनाव में भाग लेने की इच्छा रखने वाले ये विधायक पटना में टिकट के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

नामांकन के अंतिम दिन, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में गोह से विधायक बने भीम सिंह यादव, नबीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह डबलू और रफीगंज के विधायक मो. नेहालुद्दीन का टिकट काट दिया गया है. इन तीनों स्थानों से राजद ने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. टिकट न मिलने के कारण ये तीनों विधायक घर पर ही बैठे हैं. उनका कहना है कि पार्टी को उनकी आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण उन्हें टिकट से वंचित किया गया, जबकि वे विधायक रहते हुए भी राजद के लिए कार्य करते रहे. इस बात की भनक पहले नहीं लगी थी कि उनका टिकट काटा जाएगा. चर्चा है कि पार्टी ने अंतिम समय में यह निर्णय लिया, जिससे ये चुनाव नहीं लड़ सके.

गोह से विधायक रहे भीम यादव ने पहली बार 2000 में नबीनगर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और तब नबीनगर की राजनीति में हलचल मच गई थी. वर्ष 2005 में भी वे फिर से विजयी हुए. अक्टूबर 2005 के चुनाव में विजय कुमार को करीब पांच हजार मतों से हराया था.

विशेष | मुस्लिम वोटबैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश, कौन पड़ेगा किस पर भारी

माया का गेम प्लान लगाएगा अखिलेश कुनबे में सेंध?

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में लखनऊ में पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर हुई महारैली के बाद राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है. अब उन्होंने अपने पुराने मुस्लिम वोटबैंक को फिर से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.

मायावती ने बुधवार को कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है. राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस कदम से समाजवादी पार्टी (सपा) और इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है.

> **विश्लेषकों की राय-** राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम का कहना है कि मायावती के एक्टिव होने से पश्चिमी यूपी में सपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट प्रभावशाली हैं. वहीं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह का मानना है कि मायावती की रणनीति का सीधा असर इंडी गठबंधन पर पड़ेगा. उन्होंने कहा, अगर मुसलमान बसपा के साथ लौटता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान सपा को होगा. त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनी तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुसलमान तब तक बसपा पर भरोसा नहीं करेगा, जब तक मायावती साफ तौर पर यह नहीं कहतीं कि वह बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी.

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में बसपा की निष्क्रियता के कारण मुस्लिम वोट सपा की ओर शिफ्ट हो गया था. 2017 तक पश्चिमी यूपी में बसपा का मुस्लिम वोटबैंक मजबूत माना जाता था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता लगभग पूरी तरह अखिलेश यादव के साथ चले गए थे. वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम का कहना है कि मायावती अब अखिलेश यादव की मुस्लिम मुद्दों से दूरी का फायदा उठाना चाहती हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार के नतीजों के बाद मुसलमानों का रुख बदल सकता है, और मायावती इसे भांप चुकी हैं.

इस बैठक में कई अनोखी बातें देखने को मिलीं. पहली और दूसरी पंक्ति में सिर्फ मुस्लिम नेता बैठे थे, जबकि पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेता तीसरी पंक्ति में मौजूद थे. जानकारों के मुताबिक, बैठक में मुस्लिम पदाधिकारियों को 'पीला लिफाफा' दिया गया, जिसमें बसपा सरकारों द्वारा मुसलमानों के लिए किए गए कार्यों का विवरण था. इसमें यह भी लिखा गया था कि पहली और दूसरी बसपा सरकार सिर्फ मुसलमानों की वजह से बनी और टूटी थी.